भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2866
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

†2866. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का योजना-वार/जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के लिए आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का योजना-वार/जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करते समय निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यों का वर्ष-वार/योजना-वार/जिले-वार ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या उक्त योजनाओं में से किसी में समय और लागत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत और अमृत 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम और एसबीएम 2.0), शहरी परिवहन (यूटी) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

<u>अमृत और अमृत 2.0</u>:

महाराष्ट्र में अमृत के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान 933.56 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से 781.44 करोड़ रुपए के कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं (अनुलग्नक-।)।

महाराष्ट्र में अमृत 2.0 के अंतर्गत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 31,722.23 करोड़ रू. (संचालन एवं रखरखाव लागत सहित) की कुल 303 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है (अनुलग्नक ॥)। 19,969.95 करोड़ रू. की लागत वाली 181 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए गए हैं।

अमृत एवं अमृत 2.0 के अंतर्गत धनराशि जिला-वार नहीं बल्कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की जाती है।

अमृत के अंतर्गत 3534.08 करोड़ रू. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता में से 3356.19 करोड़ रू. जारी किए गए, जिसमें से 3065.01 करोड़ रू. का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार, अमृत 2.0 के अंतर्गत 9310 करोड़ रू. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता में से 1831.96 करोड़ रू. जारी किए गए, जिसमें से 1514.04 करोड़ रू. का उपयोग किया गया है।

एससीएम:

महाराष्ट्र राज्य में 8 स्मार्ट शहर हैं और पिछले 5 वर्षों में जारी कुल केंद्रीय हिस्सा 3822 करोड़ रू. है, जिसमें से 3797 करोड़ रू. का उपयोग किया जा चुका है। इसका ब्यौरा अनुलग्नक-॥। में दिया गया है।

<u>एसबीएम</u>:

एसबीएम-यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि वार्षिक आधार पर नहीं बल्कि पूरी मिशन अवधि के लिए आवंटित की जाती है। महाराष्ट्र को आवंटित और जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रू. में)

मिशन चरण	मिशन आवंटन	पिछले पांच वर्षों में जारी धनराशि	
		2019-20 to 2023-24	2024-25 (05.12.2024 तक)
एसमबीएम-यू (2014-2021)	1677.80	602.78	0.00
एसबीएम-यू 2.0	3758.50	791.81	0.00

(2021-2026)			

शहरी परिवहन: पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम इक्विटी भागीदारी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में क्रियान्वित की जा रही मेट्रो परियोजनाओं और भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि का ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों, जलवायु संबंधी चुनौतियों, अपेक्षित मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने में देरी तथा जटिल शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए अनुभवी और तकनीकी रूप से कुशल ठेकेदारों की कमी आदि के कारण कभी-कभी लंबी अवधि वाली बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं विलंबित हो जाती हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास एससीएम के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राज्य स्तर पर, मिशन कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) के बोर्डों में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक नियमित आधार पर संबंधित शहरों में प्रगति की निगरानी करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 100 स्मार्ट शहरों/यूएलबी के कार्य-निष्पादन का आकलन करने और जहाँ भी आवश्यक हो, उन्हें विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, समीक्षा बैठकों, क्षेत्र के दौरों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन आदि के माध्यम से राज्यों / स्मार्ट शहरों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है।

अमृत परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके शहरी स्थानीय निकायों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए अमृत और अमृत 2.0 पोर्टल हैं। मिशन दिशानिर्देशों के दायरे में गठित शीर्ष समिति समय-समय पर अमृत मिशन की समीक्षा, निगरानी और पर्यवेक्षण करती है। राज्यों में अमृत के तहत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) की स्थापना का प्रावधान है। आईआरएमए रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है।

*****

अनुलग्नक- I

'महाराष्ट्र में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं' के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले 5 वर्षों के दौरान अमृत के अंतर्गत महाराष्ट्र में शुरू की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	शहर	शीर्षक	क्षेत्र	लक्ष्य	परियोजना लागत (करोड़ रू में)	वास्तविक प्रगति (% में)	वास्तविक रूप से पूर्ण (करोड़ रू. में)
1	धुले	धुले अक्कलपाड़ा जलापूर्ति	जलापूर्ति	कार्य पूर्ण	169.13	100	169.13
2	पुणे	पुणे हरित स्थान 17-18	अन्य (पार्क)	कार्य पूर्ण	2	100	2.00
3	बदलापुर	बदलापुर सिटी सीवरेज परियोजना	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	संविदा दी गई	47.15	85	40.08
4	कल्याण डोंबिवली	कल्याण डोंबिवली जलापूर्ति	जलापूर्ति	संविदा दी गई	194.2	65	126.23
5	उल्हासनगर	उल्हासनगर सीवरेज परियोजना फेज़ II	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	कार्य पूर्ण	12.92	100	12.92
6	पनवेल	पनवेल न्हावा शेवा जलापूर्ति	जलापूर्ति	संविदा दी गई	173.27	99	171.54
7	चंद्रपुर	चंद्रपुर अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	कार्य पूर्ण	78.93	100	78.93
8	नवी मुंबई	सीवरेज - नई परियोजना आरआरडब्ल्यूडब्ल्यू	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	कार्य पूर्ण	10.43	100	10.43
9	ठाणे	सीवरेज - नई परियोजना	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	कार्य पूर्ण	25.73	100	25.73
10	अहमदनगर	सीवरेज - नई परियोजना	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	संविदा दी गई	32.43	40	12.97
11	बर्शी	जोन 1 और 2 में सीवरेज परियोजना	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	संविदा दी गई	12.25	73	8.94
12	धुले	सीवरेज -	सीवरेज और	संविदा दी गई	45.71	52	23.77

क्र. सं.	शहर	शीर्षक	क्षेत्र	लक्ष्य	परियोजना लागत (करोड़ रू में)	वास्तविक प्रगति (% में)	वास्तविक रूप से पूर्ण (करोड़ रू. में)
		मैनहोल निर्माण	सेप्टेज प्रबंधन				
13	हिंगनघाट	सीवरेज - घरेलू सेवा कनेक्शन प्रदान करना	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	संविदा दी गई	18.25	42	7.67
14	जलगांव	सीवरेज - नई परियोजना	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	संविदा दी गई	10.25	85	8.71
15	नागपुर	जलापूर्ति -नई परियोजना	जलापूर्ति	संविदा दी गई	37.17	89	33.08
16	परभणि	जलापूर्ति -नई परियोजना	जलापूर्ति	संविदा दी गई	27.89	95	26.50
17	धुले	धुले जलापूर्ति वलवाडी डब्ल्यूटीपी से तुलसीराम तक 300 मिमी व्यास की डीआई पाइपलाइन बिछाना और रॉ वाटर पंप हाउस के लिए 33 के.वी. लाइन का निर्माण	जलापूर्ति	संविदा दी गई	8.47	70	5.93
18	पनवेल	जलापूर्ति - एएमआर मीटर	जलापूर्ति	संविदा दी गई	18.25	60	10.95
19	वसई विरार सिटी	वसई विरार बल्क फ्लो मीटर	जलापूर्ति	संविदा दी गई	9.13	65	5.93
	कुल				933.56		781.44

***

अनुलग्नक - II

'महाराष्ट्र में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं' के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के भाग (क) से (ङ.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

महाराष्ट्र में अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	जिला	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित टीपीसी (करोड़ में)
1	अहमदनगर	6	314.10
2	अकोला	6	1114.64
3	अमरावती	4	1114.95
4	औरंगाबाद	5	3915.69
5	बीड	3	60.00
6	भंडारा	8	131.59
7	बुलडाना	14	562.86
8	चंद्रपुर	18	1223.10
9	धुले	5	909.55
10	गढ़चिरोली	3	138.10
11	गोंदिया	2	278.00
12	जलगांव	33	2357.66
13	जालना	1	48.63
14	कोल्हापुर	14	914.33
15	लातूर	3	635.41
16	नागपुर	11	2637.01
17	नांदेड़ वाघला	10	684.21
18	नंदुरबार	1	31.22
19	नासिक	13	1402.16
20	उस्मानाबाद	7	633.56
21	पालघर	6	1174.91
22	परभणि	2	573.61
23	पुणे	14	2615.44
24	रायगढ़	19	747.98
25	रत्नागिरी	3	59.27
26	सांगली	4	360.94
27	सतारा	13	522.77
28	सिंधुदुर्ग	1	1.25
29	सोलापुर	6	624.67
30	ठाणे	54	5164.56
31	वर्धा	9	431.36
32	वाशिम	1	42.16
33	यवतमाल	4	296.54
कुल योग		303	31722.23

'महाराष्ट्र में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं' के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के भाग (क) से (ङ.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

केंद्र द्वारा जारी की गई कुल धनराशि और स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के लिए उपयोग सहित पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

जिला	**स्वीकृत स्मार्ट शहर**	**पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष में केंद्र द्वारा जारी धनराशि**	**केंद्र द्वारा जारी कुल धनराशि**	**भारत सरकार की धनराशि का उपयोग**
औरंगाबाद	औरंगाबाद	294	490	490
ठाणे	कल्याण-डोंबिवली, ठाणे	588	980	958
नागपुर	नागपुर	257	453	453
नासिक	नासिक	233	429	426
पुणे	पिंपरी-चिंचवाड़, पुणे	588	980	980
सोलापुर	सोलापुर	294	490	490
		2254	3,822	3,797

****

अनुलग्नक-IV

'महाराष्ट्र में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं' के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(क) भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम इक्विटी साझेदारी के तहत महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वित की जा रही मेट्रो परियोजनाओं का ब्यौरा:-

क्र. सं.	मेट्रो परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	कार्यान्वयन एजेंसी	लंबाई	परियोजना लागत (करोड़ रू. में)
1	पुणे मेट्रो फेज़ -I	दिसंबर, 2016	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा मेट्रो)	33.28 कि.मी.	13,656.22
2	पुणे मेट्रो फेज़ -I पीसीएमसी से निगरी तक विस्तार परियोजना	अक्टूबर, 2023	-वही-	4.413 कि.मी.	910.18
3	पुणे मेट्रो फेज़ -I स्वरगते से कात्रज तक विस्तार परियोजना	सितंबर, 2024	-वही-	5.464 कि.मी.	2,954.53
4	नागपुर मेट्रो फेज़ -I	अगस्त, 2014	-वही-	40.022 कि.मी.	9,759.79
5	नागपुर मेट्रो फेज़ -II	दिसंबर, 2022	-वही-	43.80 कि.मी.	6,708.00
6	मुंबई मेट्रो लाइन -III	जुलाई, 2013	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल)	33.50 कि.मी.	37,276.00

(ख) पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र में मेट्रो परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि का ब्यौरा:
पुणे मेट्रो फेज़-I

(करोड़ रू. में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
इक्विटी	381.00	100.00	173.91	95.09	0	0
अधीनस्थ ऋण	122.86	100.00	50.00	2.14	0	0
पास थ्रू एसिसटेंस	1,500	100.00	2971.00	1260.50	0	0
कुल	2,003.86	300.00	3,194.91	1,357.73	0	0

पुणे मेट्रो विस्तार परियोजनाएं:- शून्य
नागपुर मेट्रो फेज़ -I

(करोड़ रू. में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
इक्विटी	199.03	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
अधीनस्थ ऋण	110.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

पास थ्रू एसिसटेंस	1550.00	302.00	0.00	0.00	599.06	0.00
कुल	1859.03	371.85	0.00	0.00	599.06	0.00

नागपुर मेट्रो फेज़-II

(करोड़ रू. में)

	2023-24	2024-25
इक्विटी	500.00	0
अधीनस्थ ऋण	100.00	0
पास थ्रू एसिसटेंस	0.00	0
कुल	600.00	0

मुंबई मेट्रो लाइन-3

(करोड़ रू. में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
इक्विटी	650.00	100.00	296.00	199.10	358.83	804.47
अधीनस्थ ऋण	260.52	50.00	104.80	80.46	236.00	103.85
पास थ्रू एसिसटेंस	3,498.59	1,225.00	2,011.29	227.66	3,300.00	3,338.67
कुल	4,409.11	1,375.00	2,412.09	507.22	3,894.83	4,246.99

***